

PROJECT SYNDICATE

THE WORLD'S OPINION PAGE

GLOBAL HEALTH & DEVELOPMENT



ASIT K. BISWAS

Asit K. Biswas is Distinguished Visiting Professor at the Lee Kuan Yew School of Public Policy in Singapore and co-founder of the Third World Center for Water Management. He was a founder of the International Water Resources Association and World Water Council.



AHMET C. BOZER

Ahmet C. Bozer is Executive Vice-President of the Coca-Cola Company and President of Coca-Cola International.

SEP 18, 2014

पानी का मूल्य क्या है

सिंगापुर/अटलांटा - उन्नीसवीं सदी के शुरू में, लॉर्ड बायरन ने *डॉन जुआन* में लिखा था कि "जब तक दर्द नहीं सिखाता तब तक आदमी को वास्तव में पता नहीं चलता कि अच्छे पानी का मूल्य क्या है।" लगभग 200 साल बाद भी, ऐसा लगता है कि मानवता अभी भी पानी का मूल्य नहीं समझती, जिसके उदाहरण लगभग हर जगह दशकों से खराब जल प्रबंधन और प्रशासन में मिलते हैं। लेकिन आसन्न जल संकट की अनदेखी करना अधिकाधिक कठिन होता जा रहा है - खास तौर से उनके लिए जो पहले ही इसका प्रभाव महसूस कर रहे हैं।

इससे सुनिश्चित होने के लिए, हाल के सालों में जल प्रबंधन में कुछ सुधार किए गए हैं। लेकिन वे लगातार ऐसी धीमी गति से आए हैं कि समस्या का प्रभावी ढंग से समाधान नहीं कर सकते।

इसकी प्रगति को गति देने में मदद करने के लिए, नेस्ले, कोका कोला, एसएबीमिलर, और यूनीलीवर जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ - जो लंबे समय से अपने निवेशकों के सामने पानी की कमी से उनके कारोबार, और निश्चित रूप से उन समुदायों के लिए खतरे पर जोर दे रही हैं, जिनमें वे

काम कर रही हैं - पानी की उपलब्धता, गुणवत्ता और स्थिरता में सुधार करने के लिए काम कर रही हैं। उनकी सफलता के लिए अभिनव रणनीति की ज़रूरत होगी जो पानी से संबंधित समस्याओं के बारे में आरोपित धारणाओं - और दृष्टिकोण - को रोकेगी।

उदाहरण के लिए, यह प्रचलित दृष्टिकोण, सटीक होने के बावजूद, बहुत संकीर्ण है कि दुनिया को अच्छे जल प्रबंधन की ज़रूरत है। जल प्रबंधन को अपने आप में लक्ष्य - एकल संस्करण-समस्या के लिए एकल-संस्करण समाधान - के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे अनेक लक्ष्यों के लिए साधन के रूप में माना जाना चाहिए, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक और आर्थिक विकास शामिल है।

इस व्यापक संदर्भ में देखने पर, उनमें से अनेक मानदंडों, प्रथाओं, और प्रक्रियाओं को बदलने की ज़रूरत है जिनका इस्तेमाल फ़िलहाल समुदायों के जल संसाधनों के लिए किया जा रहा है। इस बात पर विचार करते हुए कि जल संसाधनों को, उदाहरण के लिए, खाद्य और ऊर्जा से प्रतिस्पर्धा से अलग नहीं किया जा सकता, इस पर स्वतंत्र रूप से कार्रवाई नहीं की जा सकती। बहुमुखी समस्याएँ बहुमुखी समाधानों की माँग करती हैं।

मामलों को और ज़्यादा उलझाते हुए, जनसांख्यिकीय परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, देशों के भीतर और देशों में प्रवास, भूमंडलीकरण, व्यापार उदारीकरण, और विकासशील देशों में मध्य वर्ग के तेज़ी से विस्तार के कारण, अगले कुछ दशकों में इन समस्याओं की पृष्ठभूमि काफ़ी ज़्यादा बदलने की संभावना है। इन बदलावों के साथ तीव्र औद्योगिकीकरण और विज्ञान और प्रौद्योगिकी (खास तौर से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी) के क्षेत्र में प्रगति होगी, और इनसे आहार की आदतों और खपत के पैटर्न में बदलाव आएगा।

नतीजतन, पानी की खपत के पैटर्न काफ़ी हद तक बदल जाएँगे, जिनमें परोक्ष रूप से कृषि, और ऊर्जा के माध्यम से, और भूमि के इस्तेमाल में बदलाव शामिल है। निश्चित रूप से, ये संबंध दुनिया के अनेक हिस्सों में पहले ही स्पष्ट हो गए हैं। उदाहरण के लिए, अनेक एशियाई देशों में - जिनमें भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल हैं - अधिक निकासी और ऊर्जा में सहायता राशि के कारण भूजल स्तर में खतरनाक दर से गिरावट आ रही है।

भारत के लिए, समस्या 1970 के बाद के दशक में शुरू हुई, जब प्रमुख दाताओं ने सरकार को, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ़्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया। शुरू में सहायता राशि प्रबंध के योग्य थी, और इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में खाद्य उत्पादन बढ़ाने के उनके लक्ष्य हासिल किए गए।

लेकिन इस नीति ने किसानों द्वारा पंप पानी की मात्रा को सीमित करने के लिए प्रोत्साहन राशि हटा दी। उन्हें केवल वास्तविक पंप स्थापित करने में निवेश करना था - और उन्होंने यह स्वेच्छा से किया, जिसके परिणामस्वरूप आज 23 मिलियन पानी के पंप मौजूद हैं।

इस फ़िज़ूलखर्ची का भूजल स्तर पर बहुत ख़राब असर हुआ, और इसके कारण उन नलकूपों को और ज़्यादा गहरे स्तर पर लगाने के लिए बाध्य होना पड़ा जिनसे पानी पंप किया जाता था। जल प्रबंधन के लिए तीसरी दुनिया का केंद्र के अनुसार भारत में केवल पिछले दशक में ही पानी पंप करने के लिए ज़रूरी बिजली की मात्रा दोगुनी - और, कुछ मामलों में, तिगुनी तक - हो गई है, क्योंकि नलकूपों का पानी 10-15 मीटर (32-50 फुट) से खिसककर 200-400 मीटर (650-1300 फुट) गहरे तक चला गया है। बढ़ती हुई गहराई के कारण हर पंप के लिए 3-4 गुना ज़्यादा अश्वशक्ति की ज़रूरत होती है।

इन स्थितियों में, राज्यों के जल मंत्रालयों के पास भूजल सिंचाई को स्थायी बनाने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। बिजली की सहायता राशि में निरंतर बढ़ोतरी के साथ, जो ऊर्जा क्षेत्र को निचोड़ रही है, ज़्यादा-पम्पिंग को काबू में करने के लिए प्रभावी नीतियाँ बनाना मुश्किल है।

जल क्षेत्र को ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में विकास पर प्रतिक्रिया करनी होगी, जिस पर, घनिष्ठ संबंध होने के बावजूद, इसका बहुत सीमित नियंत्रण है। अगर ज़्यादा न कहा जाए, तो विभिन्न क्षेत्रों की नीतियों का प्रभावी ढंग से समन्वय करना मुश्किल होगा।

यह चुनौतीपूर्ण लग सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इन चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है - अगर, हमारे नेता उनसे निपटने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएँ। हमारे पास पहले ही ज़रूरी प्रौद्योगिकी, जानकारी, अनुभव, और यहाँ तक कि वित्त-पोषण भी है। मज़बूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, जानकारी-युक्त जनता से निरंतर दबाव, और अंतःक्षेत्रीय सहयोग करने वाले जल पेशेवरों और संस्थानों से "कर सकते हैं" दृष्टिकोण के साथ, दुनिया की जल प्रबंधन की समस्याओं से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

लेकिन हमें अभी कार्रवाई करनी होगी। समय - और पानी - चला जा रहा है।

<https://www.project-syndicate.org/commentary/asit-k--biswas-and-ahmet-c--bozer-warn-that-current-efforts-to-improve-the-management-of-water-scarcity-are-woefully-inadequate/hindi>